बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 146 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 24 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन बी-2/370, सुल्तानपुरी दिल्ली-86

रंधावा सुसाइड केस में अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा- पंजाब के सांसद लिखकर दें, जांच सीबीआई को सौंप दूंगा

नई दिल्ली । पंजाब के वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या का मामला अब लोकसभा तक पहुंच गया है। पंजाब सरकार के मंत्री लालजीत भुल्लर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोपों के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में सीबीआई जांच के साफ संदेश दिए हैं। सोमवार को कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने लोकसभा में रंधावा की मौत का मुद्दा उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- यह पंजाब राज्य का विषय है, लेकिन अगर पंजाब के सभी सांसद मुझे इस मामले में लिखित अनुरोध देते हैं, तो मैं तुरंत यह केस सीबीआईको ट्रांसफर करने के निर्देश दे दूंगा।

‘खीर सेरेमनी’ संग दिल्ली के बजट सत्र का आगाज, विधायकों के निलंबन पर आप का बहिष्कार

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। रेखा सरकार दूसरी बार बजट पेश करने जा रही है। बजट सत्र की शुरुआत खीर सेरेमनी के साथ की गई। दिल्ली बजट सेशन 2026 से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और अन्य लोगों के साथ खीर सेरेमनी की, जहां स्कूली छात्राओं को खीर खिलाई गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, बजट 2026-27 यह हमारी सरकार का दूसरा बजट है। यह दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला बजट है। यह दिल्ली के लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। यह दिल्ली के विकास को अधिक गति देगा। पीएम नरेंद्र मोदी के सर्वाधिक दिन तक सरकार चलाने (8931 दिन) के रिकॉर्ड बनाने के विषय पर दिल्ली विधानसभा में अभिनंदन प्रस्ताव पास हुआ। संकल्प से सिद्धि पर विभिन्न सदस्यों ने बोलते हुए मंत्रियों और विधायकों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा पीएम ने बहुत सारी परिभाषाएं बदल दी, ईमानदारी किसे कहते हैं, सबको सिखाया, निष्ठा, देश का मान-सम्मान, देश विदेश नीति से देश का भविष्य सुरक्षित रखा है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र का अभिनंदन प्रस्ताव पास करने की प्रस्तावना की।विधानसभाआ अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने काम से देश और दुनियाभर में भारत का मान बढ़ाया है, उन्होंने आशीष सूद की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन प्रस्ताव के लिए सदस्यों की सहमति मांगी, जिसका ध्वनिमत से सभी सदस्यों ने समर्थन किया। वहीं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन सदन से बायकॉट किया है, विपक्ष के चार विधायकों को पिछले शीतकालीन सत्र से निष्कासन बरकरार रखने पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों

ने विरोध किया है। सदन में अनुपस्थित हैं। पिछले विधानसभा सत्र में भी पहले दिन के बाद विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी सदन से गायब रही थीं। 5 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण में बाधा डालने और हंगामा करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के चार विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह को सदन से मार्शल आउट और निलंबित कर दिया गया था।

विपक्ष की आवाज दबाने के अलावा कोई काम नहीं- आतिशी

वहीं, बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर आम आदमी का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आप विधायक आतिशी ने कहा, विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। विपक्ष की भूमिका होती है सरकार को जनहित के मुद्दों के बारे में बताना लेकिन भाजपा ने पिछले 1 साल में विपक्ष की आवाज दबाने के अलावा कोई काम नहीं किया। यह कैसा लोकतंत्र है। वे विधानसभा का सत्र क्यों बुला रहे हैं, जब विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है।

बजट से पहले सरकार के बड़े संकेत

दिल्ली का बजट आने से पहले सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं के साफ संकेत दे दिए हैं। इस बार महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण और आधुनिक परिवहन पर खास जोर रहने वाला है, जिससे आम लोगों को सीधे असर देखने को मिल सकता है। दिल्ली में बजट से पहले सरकार की तैयारियों और संकेतों ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इस बार का बजट महिलाओं के स्वास्थ्य, बेहतर इलाज, प्रदूषण नियंत्रण और ई-परिवहन जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, बजट का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता है। इसमें अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत करना, नई सेवाएं शुरू करना और स्वास्थ्य ढांचे में सुधार शामिल है।

पिछले से बड़ा हो सकता है ये बजट

पिछले साल 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था, जो उससे पहले के 76 हजार करोड़ रुपये से 31.5 फीसदी ज्यादा था। इस बार का बजट इससे भी बड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर, बजट से पहले सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं जो आम जनता की उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं, अब नजर इस बात पर रहेगी कि घोषणाएं जमीन पर कितनी उतरती हैं।

नई दिल्ली में पीएनजी कनेक्शन का विस्तार तेज, एनडीएमसी ने तीन महीने के लिए सड़क शुल्क किया माफ

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने बड़ा फैसला लिया है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के जरिए पाइप वाली प्राकृतिक गैस कनेक्शनों के विस्तार को तेज करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. वर्तमान स्थिति और जनहित को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है. जिसका उद्देश्य आईजीएल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में पीएनजी कनेक्शनों का तेजी से विस्तार सुनिश्चित करना है. इस पहल से राजधानी के कई इलाकों में गैस कनेक्शन की उपलब्धता बढ़ेगी और लंबित कार्यों में तेजी आएगी.पालिका परिषद के निर्देशों के अनुसार,पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के दौरान लगने वाला सड़क बहाली शुल्क सर्कुलर जारी होने की तारीख से तीन महीने के लिए माफ कर दिया गया है. इस फैसले से परियोजनाओं की लागत कम होगी और काम को तेजी से पूरा

करने में मदद मिलेगी.

स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम

यह निर्णय न केवल बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा, बल्कि लोगों के बीच स्वच्छ और सुविधाजनक ईंधन के उपयोग को भी प्रोत्साहित करेगा. पीएनजी को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प माना जाता है, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है.

24 घंटे में मिलेगी सड़क काटने की अनुमति

एनडीएमसी ने यह भी निर्देश दिया है कि आईजीएल को पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क काटने की अनुमति आवेदन मिलने के 24 घंटे के भीतर दी जाएगी. इसके साथ ही काम को तुरंत शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि प्रक्रियात्मक देरी खत्म हो और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे.

काम में तेजी के लिए संसाधनों की पूरी तैनाती

आईजीएल को निर्देश दिया गया है कि वह पर्याप्त जनशक्ति और संसाधनों को तैनात कर प्राथमिकता के आधार पर काम पूरा करें. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि खुदाई के बाद सभी हिस्सों को समय पर भरकर सुरक्षित किया जाए, जिससे आम जनता को कोई परेशानी न हो.

सड़क बहाली को भी दी गई प्राथमिकता

पालिका परिषद के सड़क डिवीजनों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभावित सड़कों की मरम्मत तय समय सीमा के भीतर प्राथमिकता के आधार पर करें. इससे यातायात में बाधा कम होगी और लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

सख्ती से लागू होंगे नए निर्देश

सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन गाइडलाइनों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. यह सर्कुलर पालिका परिषद के चेयरमेन की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है. एनडीएमसी की यह पहल राजधानी में नागरिक-केंद्रित शासन, बेहतर शहरी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. आने वाले समय में इससे लाखों लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.

4 विधायकों के निलंबित पर आप का हल्लाबोल, दिल्ली विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे विधायक

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष की नेता आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर किया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान, आप विधायकों ने पोस्टर लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने लोकतंत्र की हत्या बंद करो जैसे नारे लगाए और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। हम विधानसभा के बाहर हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है। विपक्षी विधायकों को किस आधार पर सदन से निकाला जा रहा है? अगर कोई खड़ा होकर बोलना शुरू करता है, तो उसे सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर कोई कोई मुद्दा उठाता है, तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। अगर कोई अपने क्षेत्र में कोई समस्या उठाता है, चाहे वह पानी की समस्या हो या बिजली की, तो उस पर विशेषाधिकार थोपा जाता है। यह किस तरह का तरीका है? यह विपक्ष की आवाज को दबाने का तरीका है। यह लोकतंत्र की हत्या करने का तरीका है। आतिशी ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बवाना और खानपुर जैसे इलाकों में अपराध की घटनाओं के दौरान पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती, जबकि विधायकों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया जाता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विपक्ष के बिना विधानसभा चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में चार विधायकों को निलंबित कर दिया गया था और अब उन्हें बजट सत्र में भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। इसीलिए आज सभी विधायक सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जब तक उनके चार विधायकों, संजय झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और सोमदत्त को विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, तब तक वे कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और अपना विरोध जारी रखेंगे।

पीएसी और सीएजी की रिपोर्ट से डरकर भाग रहा विपक्ष, बजट सत्र का बहिष्कार करने पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा का हमला

नई दिल्ली। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष की ओर से सदन का बहिष्कार किए जाने के विरोध में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेसवार्ता कर विपक्ष की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के साथियों ने सत्र का बायकॉट किया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना था कि जब विपक्ष को पता चला कि आज पीएसी की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट आ रही है तथा पिछले एक साल में सरकार द्वारा दिल्ली में किए गए कार्यों के बारे में बताया जाएगा और अगले एक साल की दिशा को लेकर बजट पेश होगा, तो वे इन सब बातों से घबरा गए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अपनी गलतियों का सामना नहीं कर पाने और दिल्ली में की गई

कथित चोरियों और लूट के मुद्दों से बचने के लिए विपक्ष ने सदन की कार्यवाही से दूरी बनाई और विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों से बचने के लिए विपक्ष यहां से भाग रहा है और अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रहा है। दिल्ली में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हर विभाग द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र को पैसा दिया जा रहा है ताकि विकास कार्य हो सकें। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में दिल्ली की हालत खराब हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष सत्ता में था, तब उनके आठ सदस्यों को रोज सदन से बाहर निकाल दिया जाता था, जबकि अब वही लोग नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि सरकार में कोई कमियां हैं तो उन्हें सदन में उठाया जाए और दिल्ली की जनता को बताया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता का बहुत पैसा खर्च होता है और जनता ने सभी जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, इसलिए यह सभी की जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि वे दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह रहें।

शहीद दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण, ऐतिहासिक ट्रायल रूम का भी लोकार्पण

नई दिल्ली। रेखा गुप्ता ने शहीद दिवस के अवसर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित आरसीएस कार्यालय में भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और जीर्णोद्धार किए गए ऐतिहासिक कोर्ट ट्रायल रूम का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने शहीद-ए-आजम के साहस और बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्थान अत्यंत ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यहीं भगत सिंह के मुकदमे की सुनवाई हुई थी। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट ट्रायल रूम उनके अदम्य साहस, अटूट संकल्प और गहरी राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि

स्थापित की गई प्रतिमा युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, साहस और बलिदान की भावना अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों का बलिदान देश के इतिहास में अमिट है और उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और त्याग को याद रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ऐसे आयोजन समाज में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करते हैं और लोगों को देश सेवा के लिए प्रेरित करते हैं।

मार्च में मौसम ने फिर ली करवट, दिल्ली-एनसीआर में छाए बादल और हुई बारिश

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर एक बार फिर बादलों से घिर गया। नोएडा समेत दिल्ली-एनसीआर कई इलाकों में बारिश हो रही है। जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। सुबह-सुबह मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश होने का पूर्वानुमान भारत मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 23 मार्च को बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार है। सोमवार को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। ऐसे में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। यही नहीं, दिन आसमान बादलों से घिरा रहेगा। सुबह से दोपहर के बीच गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। बदलते मौसम के चलते लोगों को दिन में गर्मी और शाम के समय हल्की ठंडक का एहसास हो सकता है। रविवार को दिनभर तेज धूप के चलते लोगों को गर्मी का अहसास हुआ। हालांकि, हवा चलने से मौसम खुशनुमा रहा। इसके अलावा, बारिश की वजह से बीते तीन दिन से सुबह-शाम की हल्की ठंड होने लगी है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29.5 और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 30, आया नगर में 29.5, लोधी रोड में 29.6 और पालम में 28.2 अधिकतम पारा दर्ज किया गया। 23 मार्च के बाद 28 तक कोई बारिश नहीं होगी। हालांकि बादलों की आवाजाही बरकरार रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 23 और 24 मार्च को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। दिल्ली में 25 मार्च को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद दिल्ली में 26, 27 और 28 मार्च को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 23 मार्च को न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। दिल्ली में 24 और 25 मार्च को न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। इसके बाद दिल्ली में 26, 27 और 28 मार्च को न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

मास्टर स्ट्रोक, गिन तो लें!

ये लो कर लो बात। कहां तो मोदी जी डायरेक्ट ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां से बात कर रहे हैं। ईद तो ईद, नौरोज तक की बधाइयां दे रहे हैं और वह भी सिर्फ राष्ट्रपति को ही नहीं, ईरान की सरकार और जनता को भी। जिनके सिर पर दिन-रात बम बरस रहे हैं, उनके लिए नये वर्ष के शांति से भरा होने की कामनाएं कर रहे हैं। और हां! अगर यह सब फोन पर ही झप्पी-पप्पी करने के बराबर ही मान लिया जाए तब भी, मोदी जी इतने पर ही रुक नहीं गए हैं। वह पश्चिम एशिया में तनाव और टकराव बढ़ने पर गहरी चिंता भी जता रहे हैं। इस इलाके में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर तमाम हमलों की निंदा कर रहे हैं। चेता रहे हैं कि ऐसी हरकतों से सारी दुनिया की खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए और दुनिया भर में कृषि निर्यातों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। होर्मुज की खाड़ी की सुरक्षा बनी रहना सुनिश्चित करने और फारस की खाड़ी में नौवहन की आजादी सुनिश्चित करने का महत्व समझा रहे हैं। इस सिलसिले में विभिन्न विश्व नेताओं से अपनी बातचीत होने का हवाला भी दे रहे हैं। और तो और उसका ज्ञान भी दे रहे हैं कि युद्ध का रास्ता चुनना किसी के भी हित में नहीं है। आखिर में इसका उपदेश भी दे रहे हैं कि सभी पक्षों को जितना जल्दी हो सके, शांति की ओर बढ़ना चाहिए। और ये नासमझ भक्ति नालायक विपक्षी उसी बीती बात पर अटके हुए हैं--क्या मोदी जी ने ईरान पर अमरीका-इस्राइल के हमले की निंदा की क्या मोदी जी ने ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई नेताओं की चुन-चुनकर हत्या किए जाने की निंदा की क्या मोदी जी ने बच्चियों के एक स्कूल समेत, ईरान में हजारों नागरिक ठिकानों पर अमरीकी-इस्राइली हमलों की निंदा की नहीं की! पहले हफ्ते न बात की न निंदा की। दूसरे हफ्ते में बात की पर निंदा नहीं की। तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन फिर बात की, पर निंदा फिर भी नहीं की। तीन हफ्ते निकाल दिए, पर निंदा फिर भी नहीं की! अब मोदी जी का विरोध करने वाले इन पप्पुओं को कोई कैसे समझाए कि यह कोई चूक नहीं, मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी का नया मास्टर स्ट्रोक! देखा नहीं, कैसे हमले के दो दिन पहले, जब मोदी जी ने इस्राइल का दौरा किया, नेतन्याहू के साथ झप्पी-पप्पी की, इस्राइल की संसद में भाषण दिया और बदले में उससे एकदम नया-निकोर मैडल वसूल किया, तब यही विरोधी क्या कह रहे थे--मोदी जी ने भारत को नेतन्याहू के पाले में भर्ती करा दिया। और जब अमरीका और इस्राइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और उसके कई नेताओं की चुन-चुनकर मार दिया और मोदी जी ने फिर भी निंदा का एक शब्द तक नहीं कहा, तब यही विरोधी शर्म-शर्म के नारे लगा रहे थे। जब मोदी जी ने पहले हफ्ते में नेतन्याहू समेत, खाड़ी देशों के नेताओं से बात की और उन पर हमलों की निंदा की, पर ईरान के नेताओं से न बात की और न ईरान पर हमले की निंदा की, तब यही विरोधी इसे विश्वासघात बता रहे थे। लेकिन, जब दूसरे हफ्ते में मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात तो की, पर बाकी सब किया लेकिन अमरीकी-इस्राइली हमले की निंदा नहीं की, तब यही विरोधी गैस की तंगी, तेल की तंगी का शोर मचा रहे थे और होर्मुज के फंदे से टैंकर छुड़ाने की गुहार लगा रहे थे। और अब जब तीसरे हफ्ते में मोदी जी ने फिर बात की है, पर हमले की निंदा अब भी नहीं की है, तो विरोधी इसकी शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे ढाई दर्जन टैंकर अब भी होर्मुज में क्यों अटके पड़े हैं और इसकी शिकायतें भी कि गैस के बाद अब तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। बस जरा विधानसभाई चुनावों का अगले महीने वाला चक्र निकल जाए! देखा, मोदी जी ने कैसे तीन हफ्ते में ही विरोधियों के तीरों को दिशा नीति से हटाकर, तेल-गैस के दाम की तरफ मोड़ दिया। पर असली मास्टर स्ट्रोक इतना ही नहीं है। सब किया पर मोदी जी ने निंदा का एक शब्द अपनी जुबान से नहीं आने दिया, डियर फ्रेंड ट्रंप और डियर फ्रेंड नेतन्याहू की दोस्ती में, बात बराबर दरार नहीं आने दी। खाड़ी वाले दोस्तों की भी दोस्ती और पुख्ता कर लिया। पर ईरान के राष्ट्रपति को भी फोन किया और उसे भी बहुत नाराज नहीं किया। नतीजा! होर्मुज में फंसे गैस के अपने दो जहाज भी निकलवा लाए। अमरीका से इसकी इजाजत भी ले आए कि भारत, एक महीने तक वह रूसी तेल खरीद सकता है, जो पहले ही जहाजों पर लदा हुआ है और समुद्र में है। और अब तक तो अमरीका ने ईरान से भी उसका तेल लेने की इजाजत दे दी है, जो पहले से जहाजों पर लदा हुआ है। बल्कि हम तो कहेंगे कि ईद-नवरोज की मुबारकबाद के बाद, मोदी जी होर्मुज से भारत के दो-चार और कंटेनर तो निकलवा ही लाएंगे। यानी लड़ने वाले भले ही लड़ते रहें, भारत तक तेल और गैस आता रहेगा, रूस और ईरान से भी और वह भी ट्रंप साहब की इजाजत से! इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या होगा! फिर भी मास्टरस्ट्रोक इतना ही नहीं है। ट्रंप-नेतन्याहू से मोदी जी की दोस्ती बनी ही रही है और ईरान वालों से भी उन्होंने ज्यादा दुश्मनी नहीं होने दी है। फिलहाल ब्रिक्स का अध्यक्ष होने से मोदी जी ने उसके मंच से अमरीका-इस्राइल के हमले की निंदा नहीं होने दी है। पर ईरान वालों को इसकी उम्मीद भी बनाए रखी है कि ब्रिक्स कम से कम अपने सदस्य के नाते ईरान पर, हमले की निंदा करेगा। और जल्दी न भी सही, तब भी कभी न कभी तो, सुलह की बात चलेगी ही और सुलह के लिए, बीच-बचाव करने वाले की जरूरत भी पड़ेगी ही। उस समय बीच-बचाव करने के लिए मोदी जी से बेहतर स्थिति में कौन होगा--जिसे हमला करने वाला भी अपना सगा माने और हमले का मुकाबला करने वाला भी अपना दुश्मन नहीं माने। आखिरकार, भागवत जी ने यूं ही थोड़े कह दिया है कि सारी दुनिया कह रही है कि इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है, तो मोदी जी का भारत ही रुकवा सकता है। मोदी जी को युद्ध रुकवाने का वैसे भी काफी एक्सपीरियंस भी तो है। चौबीस घंटे के लिए ही सही, रूस-यूक्रेन युद्ध तो मोदी जी ने रुकवाया ही था, जैसा राजनाथ सिंह तक कह चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई भी वैसे रुकवायी तो मोदी जी ने ही थी, यह दूसरी बात है कि मोदी जी ने शांति के नोबेल पुरस्कार के चक्कर में ट्रंप को इसका श्रेय छीन लेने दिया। पर इस बार नहीं। वॉर जब भी रुके इस बार मोदी जी उसे रुकवाना अपने नाम करा के रहेंगे। आखिर, विश्व गुरु की गद्दी का सवाल है। यह होगा सारे मास्टरस्ट्रोकों का मास्टरस्ट्रोक।

भारत पर युद्ध की आंच

. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से युद्ध छेड़कर पश्चिम एशिया में विनाश मचा दिया है और पूरी दुनिया में आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। 22 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान इजराइल और पड़ोसी फारस की खाड़ी के उन देशों पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने और खाड़ी देशों में तेल और गैस सुविधाओं पर जवाबी हमले करने से तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई है। युद्ध शुरू होने से पहले ही कई लोगों ने चेतावनी दी थी कि ईरान पर पूर्ण आक्रमण से क्षेत्रीय संकट उत्पन्न हो सकता है। ट्रम्प ने भी इतने लम्बे संघर्ष की कल्पना नहीं की थी लेकिन ईरान के लगातार मिसाइल हमलों ने ट्रम्प और नेतन्याहू के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब इस युद्ध की आंच भारत तक पहुंच चुकी है। घमासान के बीच भारत में भी प्रीमियम पैट्रोल और उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी सामान्य पैट्रोल और डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई। यदि तेल और गैस की सप्लाई लम्बे समय तक बाधित रही तोइसका असर आम लोगों पर पड़ना तय है। उद्योग और व्यापार जगत पहले से ही दबाव में है। भारत के लिए संकट केवल ऊर्जा का ही नहीं हैइसने सोने और हीरे से लेकर खाद और विमानन उद्योग तक कई सैक्टरों में संकटखड़ा कर दिया है। कुछ सैक्टरों पर इसका असर खासतौर पर ज्यादा है। भारत के लगभग 47.5 प्रतिशत हीरो के आयात, 63 प्रतिशत खाद, 50 फीसदी पॉलीमर और 48 प्रतिशत हाइड्रोकार्बन मिडिल ईस्ट से आता है। युद्ध संकट का असर आयात और निर्यात दोनों पर ही होगा। भारत मिडिल ईस्ट से सोना, हीरे और कीमती धातुओं जैसे कच्चे माल का आयात करता है। उन्हें देश के अन्दर ही प्रोसेस करता है। ऐसे में आयात में किसी भी तरह की रुकावट से निर्यात प्रभावित होगा। खाद का सैक्टर चिंता का मुख्य विषय बना हुआ है। मिडिल ईस्ट से आने वाली नाइट्रोजन-आधारित खाद पर अत्यधिक निर्भरता के कारण अगर सप्लाई में लंबे समय तक रुकावट रहती है तो ग्लोबल कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान जैसा देखा गया था। इन खतरों के बावजूद विश्लेषकों का कहना है कि भारत की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति (समग्र आर्थिक स्थिति) अभी भी काफी मजबूत है। यह बाहरी झटकों से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। आयात के स्रोतों में विविधता लाना और घरेलू उत्पादन को स्थानीय खपत की ओर मोड़ना जैसे उपाय इस असर को कम करने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो भले ही तेल की खबरें सुर्खियों में छाई हैं लेकिन मिडिल ईस्ट संघर्ष के दूरगामी असर कहीं ज्यादा व्यापक हैं। ये उन महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को प्रभावित करते हैं जो भारत के व्यापार, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सैक्टरों की नींव हैं।

भारत में तेल का कोई संकट नहीं है। हम रूस समेत अन्य कई देशों से तेल खरीद रहे हैं लेकिन गैस संकट की चुनौती हमारे सामने है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके बावजूद सरकार पैट्रोल पम्प पर कीमतों को समायोजित करने में अनिच्छुक हो सकती है जिससे राजकोषीय दबाव उत्पन्न होगा। यदि सामान्य पैट्रोल की कीमत बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं की जाती तो भी भारत का खर्च काफी बढ़ जाएगा। रुपया अब तक के निचले स्तर को छू चुका है। तेल और गैस की ऊंची कीमतें आयात बिल बढ़ाएंगी जिससे चालू खाते का घाटा बढ़ेगा। तेल की आसमान छूती कीमतों के चलते ही अमेरिका ने ईरानी तेल की खरीद पर लगे प्रतिबंधों को 30 दिन के लिए हटा दिया है, जबकि अमेरिका ने कई वर्षों से ईरान पर तेल प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इस छूट से वैश्विक बाजारों में लगभग 140 मिलियन बैरल तेल आएगा। ईरान को छूट देना अमेरिका की मजबूरी बन गया है। या फिर यह कोई नई चाल है। युद्ध में एक दर्जन से अधिक अमेरिकी सैनिकों की मौत, अमेरिकी एफ-35 जैसे लड़ाकू विमानों को लगातार नुकसान, खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही के चलते ट्रम्प को देश में बढ़ते राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विडम्बना यह है कि ट्रम्प जिन्होंने अमेरिका के लम्बे समय तक चलने वाले युद्धों का विरोध करने के वादे पर दो बार राष्ट्रपति चुनाव जीता। उन्होंने इजराइल के इशारे पर अमेरिका को एक विनाशकारी संघर्ष में धकेल दिया है। ट्रम्प बौखला कर अपने लक्ष्यों और समय सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं। ट्रम्प कभी कहते हैं कि वे ईरान में जमीनी युद्ध के लिए अपनी सेना नहीं भेजेंगे और कभी वे कहते हैं कि वे ईरान में जमीनी सेना भेज सकते हैं। अगर गलती से भी ट्रम्प ने अमेरिकी सेना को ईरान की जमीन पर उतारा तो वह एक अत्यंत जोखिम भरा दाव होगा। इजराइल लगातार ईरानी नेतृत्व को खत्म करने में लगा हुआ है।उसने ईरान के साऊथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला करके सीमाएं पार कर दी हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी कतर, यूएई और सऊदी अरब में गैस स्थलों पर हमले कर चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल ईरान बल्कि खाड़ी देशों के नेतृत्व से सम्पर्क बनाए हुए हैं। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का सदस्य होने के चलते कई देशों द्वारा पेश उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग को खोलने के लिए दबाव बनाना है। अगर खाड़ी देश समुद्री मार्ग को खुलवाने के लिए मिलकर अपनी नौसेनाओं का इस्तेमाल करते हैं तो युद्ध बहुत जटिल हो जाएगा। बेहतर होगा कि संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाए। अमेरिका और इजराइल आक्रामकता छोड़ें तो समझौते का मार्ग निकल सकता है। अन्यथा पूरी दुनिया में बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा।

सम्पादकीय...

प्रयासों से बढ़ती उम्मीद

हर साल, हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। यह कार्यक्रम 24 मार्च 1882 की तारीख को याद करने का दिन है जब जर्मन चिकित्सक डॉ. रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, यह जीवाणु तपेदिक/क्षय रोग (टीबी) का कारण बनता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज हो जाने से टीबी के निदान और इलाज में बहुत आसानी हुई। जर्मन चिकित्सक रॉबर्ट कोच को इस खोज के लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यही कारण है कि हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन टीबी के सामाजिक, आर्थिक और सेहत के लिए हानिकारक नतीजों पर दुनिया में जन-जागरूकता फैलाने और दुनिया से टीबी के खात्मे की कोशिशों में तेजी लाने के लिए विश्व क्षय रोग दिवस मनाता आ रहा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज के सौ साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पहली बार 24 मार्च 1982 को विश्व क्षय रोग दिवस शुरू मनाने की शुरुआत की, तभी से हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। टीबी जैसी गंभीर बीमारी 21वीं सदी में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज इसके प्रभावी इलाज उपलब्ध होने के बावजूद लोग इसके लक्षणों (दो सप्ताह से अधिक खांसी, खांसी में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, तेजी से वजन घटना, भूख कम लगना, छाती में दर्द और सांस फूलना इत्यादि) को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं। इसके साथ ही, आज भी समाज में टीबी को लेकर कलंक बना हुआ है। कई लोग इस डर से जांच कराने से बचते हैं कि कहीं उनकी बीमारी का पता चलने पर सामाजिक बहिष्कार का सामना न करना पड़े। यही सामाजिक धारणा टीबी नियंत्रण और उन्मूलन की राह में एक बड़ी बाधा है और इसके कारण भारत देश में मामलों की संख्या अधिक बनी रहती है। ऐसे में सबसे अधिक आवश्यकता है व्यापक जन-जागरूकता की, ताकि लोगों को यह समझाया जा सके कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और इसका पूरा उपचार संभव है। भारत सरकार द्वारा देशभर में चलाए जा रहे विभिन्न प्रभावी अभियानों के सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर दिखने लगे हैं, जो इस दिशा में उम्मीद की किरण प्रस्तुत करते हैं। क्षयरोग उन्मूलन की दिशा में भारत की टीबी मुक्त भारत के नाम समर्पित यात्रा को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत देश ने 2015 से 2024 तक क्षय रोग (टीबी) के मामलों में उल्लेखनीय 21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, यह दर वैश्विक औसत गिरावट 12 प्रतिशत की लगभग दोगुनी है। साल 2015 में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 237 लोगों को ये बीमारी थी जो 2024 में 21 प्रतिशत घटकर प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 187 हो गई है। यह वैश्विक स्तर पर टीबी मामलों में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है, जो अन्य टीबी के उच्च-भार वाले देशों में देखी गई कमी से भी अधिक प्रभावशाली है। हालांकि ये आंकड़े अब भी देश से टीबी के उन्मूलन के लक्ष्य से काफी दूर हैं। टीबी से होने वाली मौतों में भी भारत देश में लगभग 25 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से घटकर 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर 21 हो गई है।

गैस की क़िल्लत दूर करने के आसान नुस्ख़े

डॉ. द्रोण कुमार शर्मा

इसी हफ्ते की बात है। एक दिन सुबह मेरे क्लिनिक पर एक मरीज आया। नाम उनका मैं लूंगा नहीं। नाम लूंगा तो जाति, धर्म पता चल जायेगा। लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। अब देखो राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेन्द्र मोदी का नाम लिया तो तो गुजरात में किसी मोदी की भावनाएं आहत हो गईं। कोर्ट केस हुआ और जज साहब ने दो साल की सजा भी सुना दी। सच्ची में, आजकल भावनाएं आहत होने के लिए ही होती हैं। और भावनाएं आहत होने पर कोर्ट कचहरी तो छोड़ो, दंगा तक हो जाता है। आप बस इतना ही जान लें कि वे पुराने मरीज हैं और गैस की तकलीफ से परेशान रहते हैं। मैंने उनसे पूछा, आजकल गैस कैसी है। वे बोले, पेट की गैस तो ठीक है डॉक्टर साब। पर रसोई गैस की बहुत किल्लत है। गैस का सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। बहुत लम्बी लम्बी लाइन लग रही है। उसके बाद भी गैस एजेंसी पर ब्लैक में मिल रहा है। मैंने उसे समझाया, इस काल में इसे ब्लैक नहीं कहते हैं। वह पिछले जमाने में कहते थे। आज कल नया काल है, अमृत काल और अमृत काल में इसे आपदा में अवसर कहा जाता है। कहो कि गैस एजेंसी वाला देशभक्त है, आपदा में अवसर पैदा कर रहा है। सरकार ने भी तो आपदा में अवसर तलाशा है। वैसे तो सरकार कहती है, गैस की कोई कमी नहीं है, पर गैस के दाम घरेलू सिलेंडर पर एकदम से ही साठ रुपये बढ़ा दिये हैं और कमर्शियल की तो सप्लाई ही बंद है। सरकार अपना और अपने दोस्तों का घर भर रही है, गैस एजेंसी का मालिक अपना घर भर रहा है। आपदा है, तो अवसर है। इसमें शिकायत कैसी। वह मिमिया कर बोला, डॉक्टर साब, कोई ऐसी दवा नहीं होती है जिससे गैस की बीमारी बढ़ जाये। पेट में खूब गैस बनने लगे। मैं हंसा, ज्यादा गैस क्यों चाहिए। हर समय तो गैस कम करने की दवाई मांगते हो। आज गैस ज्यादा करने की दवा लेने आए हो! मेरी जानकारी में तो कोई ऐसी दवा है भी नहीं। मेरा उत्तर सुन कर वह उदास हो गया, मैं सोच रहा हूं, अपने पेट की गैस से ही चाय बनाने लगूं। ज्यादा गैस बने तो घर की रोटी-सब्जी मेरे पेट की गैस से ही बनने लगे। पकोड़े भी तलने लगें। अगर ऐसी कोई दवा आती होती तो मैं अपने लिए तो लेता ही, बीबी-बच्चों के लिए भी ले लेता। घर में ही इतनी गैस बन जाती कि आसपास के लोगों को भी सप्लाई कर देता। वह बेचारा मायूस हो कर चला गया। जब से गैस की किल्लत हुई है, सरकार जी का नाले की गैस वाला वीडियो दुबारा वायरल होने लगा है। अगर कोई चौथी पास चाय वाला नाले की गैस से चाय बनाने लगता है तो उन मरीज महोदय द्वारा पेट में बनने वाली गैस से खाना बनाने की कल्पना करना गलत कैसे हो सकता है। और कहते हैं, मुसीबत ही अविष्कार की जननी है। तो हमारे सरकार जी इस मुसीबत की घड़ी में यह भी अविष्कार कर दें कि मुंह से निकलने वाली डकार और पीछे से छोड़ी जाने वाली गैस (पाद) से भी चाय-पकोड़ी बनाई जा सकती है तो आश्चर्य की बात नहीं है। सरकार जी हैं तो मुमकिन है। सबकुछ मुमकिन है, और वे कुछ भी बोल सकते हैं।

वैसे सरकार जी और उनके मंत्री मान ही नहीं रहे हैं कि रसोई गैस की कोई कमी है भी। यह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आधुनिक तरीका है। तरीका यह है कि उसे प्रॉब्लम मानो ही मत। और जब प्रॉब्लम है ही नहीं तो उसको सॉल्व करना कैसा जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं होने पर ऑक्सीजन की कमी नहीं मानी थी, अब रसोई गैस का सिलेंडर न होने पर रसोई गैस की कमी भी नहीं मान रहे हैं। कहते हैं, शतुरमुर्ग कोई प्रॉब्लम आने पर ऐसा ही करता है। और सरकार जी जब इसे प्रॉब्लम मान लेंगे तो हो सकता है विदेश जा कर, और अब जब युद्ध के कारण विदेशी दौरे बंद हैं तो देश में ही कहीं किसी कोने में हमारा मज़ाक़ उड़ाएं। हँस कर, हाथ हिलाते हुए कहें कि बेटी की शादी है, बारात द्वार पर खड़ी है पर उसका स्वागत कैसे करें, मेहमानों को खाना कैसे खिलाएं। गैस का सिलेंडर तो है ही नहीं। वैसे मेरे कुछ सुझाव हैं, रसोई गैस के सिलेंडर की कमी के मद्देनज़र। सरकार चाहे तो उन पर अमल कर सकती है।

1. सरकार गैस के सिलेंडर के लिए लाइन में लगना अपराध घोषित कर सकती है। जनता को भी बात बात पर लाइन में लगने की आदत ही पड़ गई है। नोटबंदी में नोट बदलवाने लाइन में लगी। कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लगी, अस्पताल में बेड के लिए लाइन में लगी, अपनों के अंतिम संस्कार के लिए लाइन में लगी। अब गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लग रही है।

2. सरकार गैस के सिलेंडर के लिए लाइन में लगे लोगों की फोटो लेना, उन पर कार्यक्रम करना, आदि देशद्रोह घोषित कर सकती है। सरकार ऐसे अखबारों पर, ऐसे चैनलों पर जो रसोई गैस की कमी पर खबर दिखाते हैं, लाइन में लगे लोगों की तस्वीर दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बैन लगा सकती है।

3. सरकार या गोदी मीडिया गैस पर खाना बनाने के नुकसान गिना सकते हैं। वैसे सच कहें तो पका कर खाना बनाने के नुकसान बता, कच्चा खाना खाने के लाभ बता सकते हैं।

4. सरकार जी रसोई गैस के अन्य विकल्प सुझा सकते हैं, जैसे नाले से निकलने वाली गैस, पेट में बनने वाली गैस। वैसे बाद वाली गैस का श्रेय मेरे उस मरीज को जाता है, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं।

5. गोबर के उपले से बने खाने को श्रेष्ठ घोषित किया जा सकता है। गाय के गोबर के उपले पर बने खाने से विभिन्न बीमारियों के दूर रहने की और असाध्य बीमारियों के ठीक होने की शर्तिया (मैच फिक्सिंग वाली) रिसर्च करवाई जा सकती है। और बाबा जी गाय के गोबर से बने उपले का व्यापार कर सकते हैं। मुझ नाचीज को तो अभी यही कुछ उपाय सूझ रहे हैं। वैसे मुझे यह सब सुझाने की जरूरत भी क्या है। पीएमओ तो है ही, नीति आयोग भी है। पहले जब वह योजना आयोग कहलाता था, ऐसी कठिनाइयों से निपटने के लिए योजनाएं बनाता था। अब उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। अब उसका काम सरकार जी को सेफ करने के लिए, विरोधियों और जनता को ब्लेम करने के लिए नीति बनाना हो गया है।

परमाणु ठिकानों पर हमले- रणनीतिक दबाव या खतरनाक जुआ -युद्ध का बदलता स्वरूप

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब पारंपरिक सैन्य टकराव की सीमाओं को पार कर एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है,जहां परमाणु ठिकाने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध का केंद्र बनते जा रहे हैं।ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने न केवल क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है,बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़े परमाणु संकट की आशंका भी उत्पन्न कर दी है। हालिया घटनाओं में जिस तरह परमाणु संयंत्रों और अनुसंधान केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनियाँ एक और परमाणु आपदा के मुहाने पर खड़ी है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि युद्ध के 23वें दिन तक आते- आते संघर्ष की प्रकृति में स्पष्ट बदलाव दिखाई देने लगा है।पहले जहां सैन्य ठिकानों,सीमावर्ती क्षेत्रों और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा था, वहीं अब परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू हो गए हैं। इजरायल द्वारा ईरान के नतांज परमाणु सुविधा पर की गई एयरस्ट्राइक इस दिशा में एक निर्णायक कदम थी। नतांज ईरान के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र है, जहां यूरेनियम संवर्धनका कार्य होता है।इसके जवाब में ईरान ने इजरायल के डिमोना परमाणु केंद्र के आसपास मिसाइल हमले किए। यह केंद्र इजरायल की परमाणु क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों द्वारा परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना केवल सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि एक खतरनाक जुआ है, जिसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं।रेडिएशन का बढ़ता खतरा- मानवता के लिए अदृश्य दुश्मन है,परमाणु संयंत्रों पर हमले का सबसे बड़ा खतरा केवल विस्फोट नहीं,बल्कि रेडिएशन लीक है।परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व मौजूद होते हैं। यदि किसी हमले में इनका रिसाव होता है, तो उसका प्रभाव केवल तत्काल क्षेत्र तकसीमित नहीं रहता, बल्कि हवा, पानी और मिट्टी के माध्यम से हजारों किलोमीटर तक फैल सकता है।रेडिएशन के प्रभाव बेहद गंभीर होते हैं,कैंसर, जन्मजात विकृतियां, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना और दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति। चेर्नोबिल दुर्घटना और फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जिनके प्रभाव आज भी महसूस किए जा रहे हैं। यदि पश्चिम एशिया में इसी प्रकार की कोई घटना घटती है, तो उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। साथियों बात अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानें (आईएईए) की भूमिका और ताजा स्थिति को समझने की करें तो इन बढ़ती आशंकाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एजेंसी ने हाल ही में डिमोना क्षेत्र में हुए हमले के बाद स्पष्ट किया कि नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र को किसी प्रकार की क्षति के संकेत नहीं मिले हैं और विकिरण स्तर सामान्य है। यह राहत की खबर जरूर है, लेकिन यह स्थिति अस्थायी भी हो सकती है, क्योंकि युद्ध अभी जारी है और किसी भी समय हालात बदल सकते हैं।आईएईए लगातार क्षेत्रीय देशों के साथ संपर्क में है और रेडिएशन स्तर की निगरानी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल निगरानी पर्याप्त है, या वैश्विक समुदाय को इस संकट को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे साथियों बात अगर हम डिमोना और नतांज- क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण इसको समझने की करें तो डिमोना और नतांज केवल दो परमाणु केंद्र नहीं हैं,बल्कि ये दोनों देशों की सामरिक शक्ति के प्रतीक हैं। डिमोना, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित परमाणु स्थलों में गिना जाता है, इजरायल की कथित परमाणु हथियार क्षमता का आधार है। यहां अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, जैसे आयरन डोम और एरो मिसाइल सिस्टम तैनात हैं। वहीं नतांज ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हृदय है, जहां सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को समृद्ध करने का कार्य करते हैं। इन दोनों ठिकानों पर हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि विरोधी देश की रणनीतिक क्षमता को कमजोर करने का प्रयास है। साथियों बात अगर हम अमेरिका की भूमिका और बढ़ता दबाव इसको समझने की करें तो इस संघर्ष में अमेरिका की भूमिका भी बेहद अहम है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम स्थिति को और अधिक गंभीर बना देता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोलता है, तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा। यह चेतावनी केवल सैन्य धमकी नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दबाव का भी हिस्सा है।

होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है, और इसके बंद होने से विश्व अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ईरान ने भी जवाब में अमेरिकी और इजरायली ऊर्जा तथा आईटी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की चेतावनी दी है, जिससे साइबर और ऊर्जा युद्ध की संभावना भी बढ़ गई है।यदि यह संघर्ष और बढ़ता है, तो इसका सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। पश्चिम एशिया दुनिया के तेल और गैस का प्रमुख स्रोत है। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने या अस्थिर होने से तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिससे वैश्विक महंगाई और आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।भारत जैसे देशों के लिए, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि, औद्योगिक लागत में बढ़ोतरी और आर्थिक विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथियों बात अगर हम युद्ध का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव को समझने की करें तो परमाणु खतरे के बीच जीना केवल भौतिक संकट नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोग लगातार भय, असुरक्षा और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। बच्चों और युवाओं पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे एक पूरी पीढ़ी मानसिक आघात का शिकार हो सकती है।इसके अलावा, यदि रेडिएशन का खतरा वास्तविकता में बदलता है, तो बड़े पैमाने पर विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे शरणार्थी संकट और भी गहरा जाएगा। साथियों बात अगर हम क्या यह परमाणु युद्ध की ओर बढ़ता कदम है इसको समझने की करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता है वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खतरा वास्तविक है। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने परमाणु हथियारों के उपयोग का संकेत नहीं दिया है, लेकिन परमाणु ठिकानों पर हमले इस दिशा में एक खतरनाक संकेत हैं।इतिहास गवाह है कि जब युद्ध नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो परिणाम विनाशकारी होते हैं।यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं, तो यह संघर्ष एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकता है, जहां से वापसी संभव नहीं होगी। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी को समझने की करें तो इस संकट के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। संयुक्त राष्ट्र,आईएईए और अन्य वैश्विक संस्थाओं को मिलकर युद्धविराम और कूटनीतिक समाधान की दिशा में काम करना होगा।महाशक्तियों को भी यह समझना होगा कि यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा का प्रश्न है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो इसका परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी दुनियाँ,पश्चिम एशिया में चल रहा यह संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। परमाणु ठिकानों पर हमले,रेडिएशन का खतरा, ऊर्जा युद्ध और महाशक्तियों की भागीदारी ये सभी संकेत एक बड़े संकट की ओर इशारा करते हैं।हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं हुई है, लेकिन यदि जल्द ही कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला गया,तो यह संघर्ष एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकता है, जहां से वापसी असंभव हो जाएगी।दुनियाँ आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां उसे यह तय करना है कि वह शांति और सहयोग का मार्ग अपनाएगी या विनाश और संघर्ष का। यह केवल ईरान, इजरायल या अमेरिका का सवाल नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य का प्रश्न है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साय पीपलवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की तैयारियों में तेजी, डीएम ने की समीक्षा बैठक

कुशीनगर।

जनपद कुशीनगर में आगामी 31 मार्च से 02 अप्रैल 2026 तक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के सफल आयोजन को लेकर जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में नोडल अधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध और समन्वित तरीके से निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन जनपद और प्रदेश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जाएं। डीएम ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम स्थल पर टेंट, मंच, बैठक व्यवस्था समेत सभी आधारभूत सुविधाओं का कार्यादेश 25 मार्च तक जारी कर 29 मार्च तक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। साथ ही प्रतिभागियों, वक्ताओं और वीआईपी अतिथियों की सूची तैयार कर समय से आमंत्रण भेजने तथा कार्यक्रम की

विस्तृत रूपरेखा बनाने को कहा। उन्होंने शिक्षक, किसान,महिला, आशा एवं युवा सम्मेलनों के आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता, कलाकारों की उपलब्धता और मंच संचालन को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अतिथियों और भिक्षुओं के ठहरने, होटल व्यवस्था, परिवहन, भोजन, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, अग्नि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं प्रोटोकॉल के अनुरूप हों और किसी भी स्तर पर समन्वय की कमी न रहे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्रबंधन, प्रचार-प्रसार, प्रेस समन्वय, कंट्रोल रूम संचालन और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी समितियों को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम से एक दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और रन फॉर पीस कार्यक्रम की तैयारियां समय से पूरी करने को भी कहा गया। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक को पुलिस और प्रशासन के समन्वय से सुदृढ़ सुरक्षा एवं यातायात योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), उपजिलाधिकारीगण एवं सभी नामित नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

समाधान दिवस में जनसमस्याओं पर सख्ती, डीएम ने अधिकारियों को दी चेतावनी

कप्तानगंज,कुशीनगर।

तहसील सभागार कप्तानगंज में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध, निष्पक्ष एवं नियम सम्मत निस्तारण पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने निर्देश दिया कि जिन गांवों में राजस्व विवाद अधिक हैं, वहां राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी स्वयं जाकर दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सुलह-समझौते से मामलों का निस्तारण करें। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को भूमि विवाद, आपसी रंजिश और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 25 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 16 राजस्व, 1 पुलिस एवं 6 अन्य विभागों से संबंधित थे, जबकि कुछ प्रकरण संयुक्त रूप से जुड़े पाए गए। इनमें से 3 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को भेजते हुए उनकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से भूमि विवाद, वरासत, पैमाइश, सीमांकन एवं राजस्व अभिलेखों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर दिया।

तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण

समाधान दिवस के बाद जिलाधिकारी ने तहसील परिसर का औचक निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं, अभिलेखों के रख-रखाव एवं साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने न्यायालय की पत्रावलियों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

अंकेक्षण कार्य को अनिवार्य बनाए जाने पर प्रधानाचार्य परिषद की आपत्ति

कुशीनगर।

उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव भगवती सिंह से भेंट कर अंकेक्षण कार्य को अनिवार्य किए जाने के निर्णय पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। परिषद के संरक्षक श्रीनिवास शुक्ल, राजेंद्र कुमार बाजपेई, सर्वोच्च समिति के महामंत्री डॉ. रवींद्र त्रिपाठी, अध्यक्ष डॉ. मणि शंकर तिवारी एवं महामंत्री शैलेन्द्र दत्त शुक्ल ने सचिव के समक्ष कहा कि पूर्व में अंकेक्षण कार्य शिक्षक एवं प्रधानाचार्य दोनों द्वारा किया जाता रहा है, जबकि इस वर्ष इसे केवल प्रधानाचार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्यों पर विद्यालय संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं, जिससे इस कार्य के लिए पर्याप्त समय देना कठिन हो जाता है। परिषद ने यह भी अवगत कराया कि कई मूल्यांकन केंद्रों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं हैं और पूर्व में पारिश्रमिक की दर अत्यंत कम (?1 प्रति प्रति) होने के कारण भी असंतोष रहा है। ऐसे में अंकेक्षण कार्य को अनिवार्य न किए जाने की मांग की गई। इस पर सचिव भगवती सिंह ने बताया कि बीते वर्षों में मूल्यांकन में कई त्रुटियां पाई गई थीं, जिन्हें दूर करने के लिए इस वर्ष से अंकेक्षण कार्य को गंभीरता से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों के अनुभव से मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। साथ ही पारिश्रमिक को बढ़ाकर ?14 प्रति प्रति कर दिया गया है और आगामी सत्र से उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण व संकलन की जिम्मेदारी एजेंसी को सौंपने जैसे सुधारात्मक कदम भी प्रस्तावित हैं।

परिषद ने यह भी अनुरोध किया कि अपरिहार्य कारणों से अंकेक्षण कार्य नहीं कर पाने वाले प्रधानाचार्यों पर दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, जिस पर सचिव ने इसे विचारणीय बताया। जारीकर्ता के हवाले से प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मणि शंकर तिवारी, प्रदेश महामंत्री शैलेन्द्र दत्त शुक्ल एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष सूर्य प्रकाश यादव ने बताया कि परिषद लगातार शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रही है और भविष्य में भी उनके हितों की रक्षा के लिए प्रयास जारी रहेगा।

टहल रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर- कुशीनगर में गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी

नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर। कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र में एक सड़क हादसा सामने आया है। यहां पैदल टहल रहे एक युवक को पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज जारी है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामपुर गोनहा ग्राम सभा के अहिरौली टोला निवासी 26 वर्षीय प्रेमानंद गौतम रविवार को अपने घर से बाहर सड़क पर टहल रहे थे। वह मोबाइल फोन पर किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से तेज गति से आ रही बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक उसी गांव का निवासी जवाहिर प्रसाद है, जो रामपुर गोनहा के चनरहा टोला का रहने वाला है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्रेमानंद सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर व दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, उनके पैर में फ्रैक्चर होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल प्रेमानंद को उठाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।प्रेमानंद गौतम खड्डा स्थित गांधी किसान इंटर कॉलेज में जूनियर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। उनके घायल होने की खबर से परिवार में चिंता का माहौल है, वहीं क्षेत्र में भी इस घटना को लेकर चर्चा बनी हुई है।स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव की सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

टीबी उन्मूलन में जनभागीदारी से ही मिलेगी सफलता- डीएम दिव्या मित्तल

देवरिया।

विश्व टीबी दिवस से एक दिन पहले सोमवार को पूरा जिला टीबी उन्मूलन के संकल्प के साथ जागरूकता की मुहिम में डूबा रहा। पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज परिसर से निकाली गई जन-जागरूकता रैली ने शहर के लोगों को एकजुट करते हुए जन-जन का हो एक ही नारा, टीबी मुक्त हो देश हमारा का संदेश दिया। रैली को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ अनिल कुमार गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली बच्चों और स्वास्थ्य कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान टीबी के बैक्टीरिया और टीबी चैंपियन के प्रतीकात्मक पुतले भी शामिल किए गए, जो आकर्षण का केंद्र बने रहे। रैली कोतवाली रोड, जिलाधिकारी आवास, सिविल लाइन रोड, बस स्टैंड और सीएमओ कार्यालय होते हुए टीबी क्लिनिक पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में लोगों ने रैली का स्वागत किया और टीबी मुक्त भारत के संकल्प को अपना

समर्थन दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि टीबी उन्मूलन में जनभागीदारी सबसे अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है और पिछले वर्षों की तुलना में मृत्यु दर में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि अगर आम जनता सहयोग करे तो इस गंभीर बीमारी को समय से पहले खत्म किया जा सकता है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार टीबी उन्मूलन की दिशा में हर संभव कदम उठा रही है। स्वास्थ्य विभाग नए साधन और तकनीकों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जिले में टीबी मरीजों की सक्रिय रूप से खोज की जा रही है और उन्हें समय पर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जिले की उन 192 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने टीबी मुक्त होने की उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा जिले के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक

विश्व टीबी दिवस पूर्व निकाली गई जागरूकता रैली, बच्चों व स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया टीबी मुक्त भारत का संदेश

स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर सीएचओ के माध्यम से लक्षण वाले मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी और उनके बलगम के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। कार्यक्रम में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ राजेश कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉ अश्वनी पांडेय, डॉ विपिन रंजन, प्रधानाचार्य राम किंकर मिश्रा, डॉ नितीश राय, डीपीसी देवेंद्र प्रताप, चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, पीपीएम मृत्युंजय पांडेय, सहयोगी संस्था सीफार के प्रतिनिधि सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और विद्यालय के छात्र-छात्राएं शामिल रहे।

वेयरहाउस डीएम आत्महत्या- पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर गिरफ्तार, मंडी गोबिंदगढ़ में किया आत्मसमर्पण

अमृतसर (पंजाब) । पंजाब वेयरहाउस कॉरपोरेशन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले में पद छोड़ने वाले पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, भुल्लर ने मंडी गोबिंदगढ़ में आत्मसमर्पण किया है। अब पुलिस भुल्लर को अमृतसर ले जा रही है। भुल्लर ने फेसबुक पेज पर कहा कि अफवाहें फैल रही हैं कि मैं भाग गया हूं... यह सच नहीं है। मैं सच्चाई से कभी नहीं भागूंगा। मुझे देश के कानून पर पूरा भरोसा है, और न्याय व्यवस्था में भी मेरी अटूट आस्था है। मैं कहीं भागा नहीं हूं, मैं अपने पंजाब में ही हूं। सच्चाई और न्याय में विश्वास रखते हुए, मैं स्वयं मंडी गोबिंदगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहा हूं।

मान बोले-किसी को भी बचाना हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं

वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा कि मेरे लिए, पूरा पंजाब एक परिवार है। अगर पंजाब में कोई भी कानून तोड़ता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी-चाहे वह किसी भी पद पर हो, या मेरा रिश्तेदार हो, या कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो। किसी को भी बचाना हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं है। नकद लेन-देन और किसी को भी अनुचित लाभ पहुंचाने पर सख्त रोक है। पुलिस ने पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह और पीए दिलबाग सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, धमकी और साजिश की धाराओं में मामला दर्ज किया है। मृतक की पत्नी उपिंदर कौर ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़ी हैं। परिवार ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

वहीं गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में रंधावा को जहरीला पदार्थ खाते हुए देखा जा सकता है।

पत्नी ने मांगी सुरक्षा

रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर ने अपने और तीन बच्चों की सुरक्षा की भी मांग की है।

परिवार ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री भुल्लर लगातार रंधावा पर टेंडर पास करने को लेकर दबाव बना रहे थे। 13 मार्च को उन्हें बुलाकर पीटा गया, धमकियां दी गई और जबरन वीडियो बनवाया गया। इसी मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर रंधावा ने जहर निगलकर जान दे दी। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें खत्म करने और गैंगस्टरों से हमला कराने की धमकियां दी गई थीं।

परिचितों को भेजा था वीडियो

घटना से पहले रंधावा ने अपने कुछ परिचितों को एक वीडियो भेजा था, जिसमें उन्होंने दबाव और उत्पीड़न का जिक्र किया था। पुलिस ने इस वीडियो को अहम साक्ष्य मानते हुए जांच में शामिल कर लिया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। रंधावा अमृतसर और तरनतारन जिलों से जुड़े वेयरहाउस कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी पत्नी सरकारी स्कूल में विज्ञान अध्यापिका हैं और परिवार में तीन छोटे बच्चे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यदि किसी ने गलत किया है या किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी। मंत्री हो या आम व्यक्ति, कानून सबके लिए समान है। मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए गए हैं।

ईरान जंग पर मोदी बोले- असर लंबा रह सकता है - हमें तैयार रहना होगा, एकजुटता हमारी पहचान

नई दिल्ली ।

पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए। बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं है। होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। पीएम ने कहा- 'सरकार की कोशिश है कि देश में तेल-गैस संकट न हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में एक करोड़ भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।' उन्होंने बताया कि अभी 3 लाख 75 हजार भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से दो हजार भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं।

मोदी की 6 बड़ी बातें......

तेल-गैस संकट पर- पिछले एक दशक में भारत ने संकट के समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है। आज हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। इसे बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक करने का काम चल रहा है। हमारी तेल कंपनियां अलग स्टोरेज रखती हैं।

अन्न-राशन पर- हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं। उस वक्त भी ग्लोबल सप्लाई चेन में कमी आई थी। भारत के किसानों को यूरिया की एक बोरी 300 रुपए से भी कम कीमत में दिलाई गई। तेल गैस फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचें, इसके लिए सहयोगियों से संवाद कर रहे हैं।

भारतीयों की सुरक्षा- संकट की घड़ी में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। अभी 3 लाख 75 हजार भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से दो हजार भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं।

■ मोदी बोले- 3 लाख 75 हजार भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं

■ प्रधानमंत्री बोले- इस समय पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक

पॉवर सप्लाई पर- युद्ध का एक चैलेंज यह भी है कि देश में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी।

देश के पावर प्लांट में कोल स्टॉक उपलब्ध है। पावर जनरेशन से लेकर सप्लाई तक हर सिस्टम की मॉनीटरिंग की जा रही है।

एनर्जी सेक्टर पर- हम जानते है एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है। ग्लोबल नीड को पूरा करने वाला सोर्स वेस्ट एशिया है। भारत पर इस युद्ध से उत्पन्न दुष्प्रभाव का असर कम हो इसके लिए एक रणनीति से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक ग्रुप बनाया है जो हर रोज मिलता है जो आयात-निर्यात में आने वाली दिक्कतों पर निरंतर काम करता है।

जंग को लेकर- डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका स्पष्ट है। हमने गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने वेस्ट एशिया के प्रमुखों से बात की है। सभी से तनाव कम करने की अपील की है।

कॉमर्शियल जहाजों पर हमला और रुकावट अस्वीकार्य है। भारत सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

तेल बाजार को प्रभावित करने के लिए फेक न्यूज फैला रहा अमेरिका, ईरान ने ट्रंप के सभी दावों को नकारा

तेहरान । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत वाले दावों पर ईरान ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। ईरान की संसद के स्पीकर ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और फेक न्यूज के जरिए तेल और वित्तीय बाजारों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका और इसराइल मौजूदा हालात से निकलने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं की है। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है और कई मुद्दों पर सहमति बनी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी साफ किया है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि तेहरान का रुख पहले जैसा ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि कुछ मित्र देशों के जरिए अमेरिका की तरफ से बातचीत के संकेत जरूर आए थे, लेकिन ईरान ने इस पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं की।

फेक न्यूज और बाजार की बात क्यों कही गई?

गालिबाफ ने आरोप लगाया कि फेक न्यूज का इस्तेमाल तेल और वित्तीय बाजारों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसे दावे करके बाजार में भ्रम फैलाया जाता है, जिससे कीमतों पर असर पड़ता है। उन्होंने इसे अमेरिका और इसराइल की रणनीति का हिस्सा बताया।

ईरान की क्या है मुख्य मांग?

ईरान ने कहा है कि वह हमलावर देशों को पूरी तरह सजा देने की मांग करता है। गालिबाफ ने कहा कि जब तक यह लक्ष्य हासिल नहीं होता, ईरानी अधिकारी अपने सुप्रीम लीडर और जनता के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इससे साफ है कि ईरान फिलहाल अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखा रहा है।

होर्मुज और युद्ध को लेकर क्या रुख है?

विदेश मंत्रालय ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य और युद्ध खत्म करने को लेकर ईरान की शर्तें पहले जैसी ही हैं। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर ईरान के अहम ढांचे पर हमला हुआ, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। एक तरफ अमेरिका बातचीत का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान साफ इनकार कर रहा है। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी बनी हुई है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और किसी भी समय स्थिति और बिगड़ सकती है।

अमोनिया गैस टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज धराशायी, चार मजदूरों की मौत, कई गंभीर

प्रयागराज ।

फाफामऊ क्षेत्र के चंदापुर में प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर स्थित सपा नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद का कोल्ड स्टोरेज तेज धमाके के साथ धराशायी हो गया। अमोनिया गैस टैंक फटने के चलते यह हादसा हुआ है। मलबे में डेढ़ दर्जन से अधिक मजदूर दब गए। आनन फानन में सभी को बाहर निकाला गया। इसमें चार मजदूरों के मौत की बात कही जा रही है। छह की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियों के साथ कई एंबुलेंस और आसपास के थानों की पुलिस फोर्स रेस्क्यू आपरेशन में जुट गई है। हादसे के चलते मलाक हरहर में लखनऊ हाईवे पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। मौके पर जिलाधिकारी मनीष कुमा वर्मा, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मलबे में डेढ़ दर्जन से आशंका जताई जा रहा है। कई लोगों को बाहर निकालकर एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया है। फाफामऊ समेत आसपास के कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि मौके से निकाले गए चार मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी बचाव कार्य में जुट गई है। दर्जन भर से अधिक जेसीबी मलबे को हटाकर दबे हुए लोगों को खोज रही है। शाम सवा चार बजे तक तीन शव निकाले जा चुके हैं। सभी मजदूर बिहार के सहरसा जिले के बताए जा रहे हैं। एक मृतक की पहचान सहरसा के योगिय के रूप में हुई है। हादसे के समय डेढ़ दर्जन से अधिक मौजूद शीतगृह में मौजूद थे। तेज आवाज के साथ धमाका हुआ तो आसपास के लोग भी सहम गए। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद के परिवार के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने भी संभाला मोर्चा। मलबे में दबे घायलों को निकालकर पहुंचाया अस्पताल।

कोलंबिया में वायुसेना का विमान क्रैश- 110 कोलंबियाई सैनिक सवार थे, 57 को जिंदा निकाला

बोगोटा । कोलंबिया में 110 सैनिकों को ले जा रहा वायुसेना का विमान क्रैश हो गया है। कोलंबिया में सोमवार को वायुसेना का एक सैन्य विमान उड़ान भरते समय क्रैश हो गया। इस विमान में 110 कोलंबियाई सैनिक सवार थे। हादसा पेरू सीमा के पास दक्षिणी अमेजन क्षेत्र के प्यूर्टो लेगुइजामो में हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 57 सैनिकों को जिंदा बचाया गया है।

रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि एयरफोर्स का हरक्यूलिस हृ-130 विमान टेक-ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तक यह साफ नहीं है कि हादसे में कितने लोग घायल हुए या उनकी मौत हुई है। राहत और बचाव टीमों को मौके पर भेजा गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। हादसे की वजह की जांच की जा रही है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सैन्य विमान हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर हादसा है और उम्मीद जताई कि इसमें किसी की जान न गई हो। पेट्रो ने कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और जवानों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सेना को मजबूत बनाने और बेहतर सुविधाएं देने पर काम कर रही है, ताकि आगे ऐसे हादसे न हों।

पेट्रो ने कहा कि सेना के हथियार और संसाधनों को आधुनिक बनाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नागरिक या सैन्य अधिकारी इस चुनौती के अनुरूप काम नहीं कर पाए, तो उन्हें हटाया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना के लिए नए हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट विमान और एंटी-ड्रोन सिस्टम तुरंत खरीदे जाने चाहिए, ताकि जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अखिलेश यादव का मास्टरस्ट्रोक, महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना पेंशन का वादा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी बताया और कहा कि इनको समृद्ध करने के लिए स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना लाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान पीडीए शब्द पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को संबोधित करने के लिए गढ़ा था। यादव ने एक्स आधी महिलाओं के साथ अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव समेत खुद की तस्वीर साझा करते हुए कहा, आधी आबादी की पूरी आजादी व उनकी हिफाजत के साथ-साथ उनके हक-अधिकार, सशक्तिकरण व सबलीकरण के लिए हम सब सदैव कटिबद्ध-प्रतिबद्ध रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा, जब परिवार-समाज और देश को मजबूत करने वालों को सम्मान मिलता है तो उनका मान और मनोबल दोनों बढ़ता है। हम पीडीए में शामिल ए मतलब आधी आबादी अर्थात हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक-आर्थिक रूप से समान सम्मान देने और अपने पैरों पर खड़े होने व उन्हें समृद्ध करने के लिए स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना लाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पेंशन को फिर से लाकर हम महिलाओं की ताकत बढ़ाएंगे और साथ ही उन की संपूर्ण उन्नति के अपने संकल्प को निभाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कुछ नया नहीं कहा, प्रियंका बोलीं- संसद में पश्चिम एशिया पर चर्चा होनी चाहिए

नई दिल्ली । प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम एशिया पर दिए गए बयान को लेकर सवाल उठाए हैं और संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की है। प्रियंका गांधी ने सोमवार को संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, उसमें कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि देश को सिर्फ जानकारी दी गई, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर सभी पक्षों की राय सामने आनी चाहिए। उनका मानना है कि संसद में चर्चा होने से सरकार और विपक्ष दोनों अपने-अपने विचार रख सकेंगे, जिससे देश को पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलेगी।

शहीदों के सपनों को साकार करने में युवा निभाएं अग्रणी भूमिका - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 23 मार्च का दिन भारत के इतिहास में अद्वितीय महत्व रखता है। यह दिन केवल स्मरण का नहीं, बल्कि संकल्प का दिन है, जब शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हँसते-हँसते अपने प्राणों का बलिदान देकर राष्ट्र के स्वाभिमान को नई ऊँचाई प्रदान की। उन्होंने कहा कि इन अमर शहीदों की शहादत आज भी हर भारतीय के मन में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करती है। मुख्यमंत्री श्री सैनी सोमवार को नंगल, पंजाब में आयोजित 'स्वदेशी मेला एवं युवा सम्मेलन' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शहीदों के

'लोकल फॉर वोकल' केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान है— नायब सिंह सैनी

पंजाब के नंगल में शहीदी दिवस पर गूंजा राष्ट्रभक्ति का संदेश

सपनों के भारत के निर्माण का जीवंत संकल्प है। उन्होंने 'सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च' और 'स्वदेशी जागरण मंच' को इस प्रेरणादायी पहल के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में क्रांति का स्वरूप बदल चुका है। अब क्रांति तलवारों से नहीं, बल्कि

विचारों, संकल्पों और सकारात्मक प्रयासों से आती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज की क्रांति नशे के खिलाफ जनजागरण, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कहा कि 'स्वदेशी' आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। जब नागरिक स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते है, तो वे सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करते है और लाखों कारीगरों व छोटे उद्यमियों के जीवन में स्थिरता लाते है। स्वदेशी का यह मंत्र आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का मंत्र है। स्वदेशी केवल एक शब्द नहीं है बल्कि यह एक आर्थिक दर्शन है। उन्होंने कहा कि 'लोकल फॉर वोकल' केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान है। यह उत्पादों की प्रदर्शनी नहीं बल्कि हमारी स्वदेशी भावना का उत्सव है। हमने स्वदेशी के संदेश को घर- घर तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को विदेश जाने की अंधी दौड़ से बचने की सलाह देते हुए कहा कि 'डंकी रूट' जैसे अवैध और जोखिम भरे रास्ते न केवल जीवन के लिए खतरा है, बल्कि परिवारों के सपनों को भी तोड़ते है। उन्होंने कहा कि भारत में अपार संभावनाएं है और युवा अपनी प्रतिभा के बल पर देश में ही सफलता प्राप्त कर सकते है। नशे की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की यह वीर भूमि, जो कभी दूध-दही के खाने के लिए जानी जाती थी, आज नशे के सौदागरों के निशाने पर है। नशा एक सामाजिक अभिशाप है, जो व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक को कमजोर करता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और समाज में जागरूकता फैलाकर दूसरों को भी इस बुराई से मुक्त करने का संकल्प लें। उन्होंने योग, खेल और अनुशासित जीवनशैली को नशा मुक्ति का प्रभावी उपाय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदी दिवस हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें और राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा समृद्धि के लिए निरंतर कार्य करें। उन्होंने उपस्थित युवाओं से सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया कि वे स्वदेशी अपनाएंगे, नशे के खिलाफ लड़ेंगे और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने हरियाणा की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास और डेयरी उत्पाद इस मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र हैं, जो प्रदेश की प्रगति और समृद्धि का परिचायक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंगल का यह स्वदेशी मेला और युवा सम्मेलन देशभक्ति, आत्मनिर्भरता और युवा शक्ति के समागम का सशक्त मंच है। उन्होंने आयोजकों को इस सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल युवाओं को राष्ट्र निर्माण में नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगी।

'पुलिस कितनी असंवेदनशील हो गई है'...बच्ची से रेप केस की जांच के तौर-तरीके से सीजेआई भी हैरान

नई दिल्ली। गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार लगाई. शीर्ष अदालत ने पुलिस से तल्ख लहजे में कहा कि आप लोग कितने असंवेदनशील हो गए हैं. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को भी कड़े शब्दों में डांट लगाते हुए कहा कि आपने मासूम बच्ची से आरोपी की मौजूदगी में बार-बार सच बोलने का दबाव बनाया. कोर्ट ने ये भी कहा कि इतने छोटे बच्चे के मामले में जिस तरह की संवेदनहीनता दिखाई गई, वह बेहद चिंताजनक है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए रेप केस में पुलिस और मजिस्ट्रेट को खूब फटकार लगाई. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल थे. पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कई गंभीर सवाल उठाए.पीठ ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि मजिस्ट्रेट ने 4 साल की बच्ची से आरोपी की मौजूदगी में सवाल पूछे और उसे बार-बार -सच बोलो-सच बोलो बोलने का दबाव बनाया. अदालत ने कहा कि पॉक्सो के मामलों में आरोपी को बच्चे के सामने या उसके करीब नहीं रखा जा सकता और ऐसे मामलों में बच्चे की सुरक्षा और संवेदनशीलता सर्वोपरि होती है. सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की भूमिका पर भी कड़े सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि शिकायत दर्ज नहीं भी हुई थी, तब भी पुलिस को स्वतः एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी.अदालत ने पुलिस को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस कितनी असंवेदनशील हो गई है.

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि बच्ची को अलग-अलग अस्पतालों और अधिकारियों के पास ले जाया गया और मजिस्ट्रेट ने आरोपी की मौजूदगी में उससे सवाल पूछे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने परिवार से कहा कि केस आगे न बढ़ाएं, वरना उन्हें परेशानी हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश

अदालत ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और मामले के जांच अधिकारी को बुधवार को कोर्ट में पूरे रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है.अदालत ने यह भी आदेश दिया कि बच्ची के माता-पिता का दिया गया हलफनामा सीलबंद लिफाफे में रखा जाए. मजिस्ट्रेट की टिप्पणी भी सीलबंद लिफाफे में अदालत को भेजी जाए. कोर्ट ने निर्देश दिया कि हरियाणा सरकार महिला पुलिस अधिकारियों का पूरा विवरण अदालत को दे. पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि जांच अधिकारी एक महिला हैं और वो माता-पिता से केस वापस लेने के लिए कह रही थीं. जांच अधिकारी को एक अन्य POCSO केस में रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था.